LP-DC/5.00/2L

श्रीमती रेणुका चौधरी (क्रमागत) : महिला किसान का - वैसे तो इस हाउस में हमने महिला की गरिमा और मर्यादा देख ली है, मगर क्या आप जानते हैं कि महिला किसान के हालात कैसे होते हैं? There is no gender-desegregated land record. क्या कोई एग्रीकल्चरल क्रेडिट मिल रहा है? जब कभी नेचुरल डिजास्टर हो जाती है तो क्या हमें SHG loans की कोई छूट मिलती है? आपके बैंक्स वसूली तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आप यह बताइए कि आपने आज के दिन में एग्रीकल्चरल क्रेडिट में कितना खर्च किया है? आपके बैंक्स हमारे गरीब किसान के घर से, जब उसके घर पर कुछ और नहीं बचा होता तो उसके घर की चौखट तक लेकर चले जाते हैं। उसके बाद बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री वाले लोग अपनी Mercedes-Benz में देश भर में घूमते हैं। क्या आपको पता है कि मर्सिडीज़ लग्ज़री कार की ईएमआई ट्रैक्टर की ईएमआई से सस्ती है? ट्रैक्टर का क्या दाम है और क्या क्वालिटी है? क्या आपने कभी चलाकर देखा है? आज के दिन देखें, तो ट्रैक्टर का वजन कम हो गया है। ..(समय की घंटी)..जब हम खेत जोतने जाते हैं तो हमारा ट्रैक्टर उठ जाता है, क्योंकि उसके गेज में कमी आ गई है। आप देखिए कि आपने महिला किसान को कुछ नहीं दिया है। landless women, especially, *Dalit* women, expansion of higher maternity and...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Renuka*ji*, I have given double time to you. Please conclude. ...(Interruptions)...

श्रीमती रेणुका चौधरी : उपसभाध्यक्ष जी, बस एक मिनट। मैं कनक्लूड कर रही हूं। अब मैं स्वास्थ्य के बारे में क्या बताऊं? सरकार तो तंदुरुस्त लगती है, मगर पीछे से कुछ कहने के लिए तो आपने कुछ कह दिया है कि देश भर में इतने सारे इंश्यारेंस होंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि यह होने वाली बात नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) : होगा, होगा।

श्रीमती रेणुका चौधरी : आप बोलिए, लेकिन हमें झूठी उम्मीदें मत दीजिए, क्योंकि हम अपने मर्दों से आटे के डिब्बे में छिपाकर, दमड़ी-दमड़ी जोड़कर पैसों की जो बचत करते हैं, हम वह पैसा भी यह सोचकर खर्च कर लेंगे कि सरकार हमारा सहारा बनेगी। महोदय, यह होने वाली बात नहीं है। आप मुझे सारी स्कीम्स के आंकड़े दें। आपने घंटी बजा दी है, इसलिए मैं मजबूर हूं कि मैं इस पर संक्षेप में बोलूं, पर आप मुझे बताइए कि PMRPRY, इस स्कीम के अंदर आपने एक पैसा allocate नहीं किया। "प्रधान मंत्री राष्ट्रीय पकौड़ा योजना" में कहीं भी एक पैसा नहीं दिया है..(व्यवधान)..

श्री नीरज शेखर : मुझे ऑब्जेक्शन है। ..(व्यवधान)..

श्रीमती रेणुका चौधरी : महोदय, मुझे skill development पर यह कहना था कि हमें इस head के नीचे कहीं भी कुछ पैसे नहीं मिले, मगर this is the crucial part.

...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Renukaji, please conclude.

श्रीमती रेणुका चौधरी : महोदय ..(व्यवधान).. Sir, I am concluding. ...(Interruptions)...इसका फिस्कल टारगेट..(व्यवधान).. 3.2 परसेंट से उतर गया है। You have failed to deliver on the 3.2 per cent target for next year's balance. उस तरफ से अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि हमने Food Park दिया। क्या आपको food processing पर जानकारी है कि उन दिए हुए 42 Food Parks में से 4 चलते हैं, वे भी लंगड़ाते-लंगड़ाते। आपके आंकड़े देने से तो वे चार भी नहीं चल रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : रेणुका जी, मैं दूसरे सदस्य का नाम ले लूंगा, आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती रेणुका चौधरी : सर, एक मेन मुद्दा है। महिलाओ के निर्भया फंड में भी कटौती हो गई। निर्भया फंड में भी कटौती हो गई, हालांकि निर्भया क्या है? एक औरत के साथ बलात्कार होने के बाद उसको कुछ सहूलियत और छूट देने के लिए कुछ व्यवस्था रखते हैं, मगर मैं सोचती हूं कि इस निर्भया फंड को हटा ही दें, क्योंकि बलात्कार की शिकार महिला की मर्यादा का सवाल है।..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : मैं अगला नाम बोलता हूं, श्री अनिल देसाई।

श्रीमती रेणुका चौधरी : * और गृह मंत्री, जिनको हमारी रक्षा करनी चाहिए, जिन्हें कानून बनाना चाहिए, वे भी ट्वीट करते हैं। अगर इस हाउस में ये हालात हैं, तो सड़क पर ..(व्यवधान)..क्या इशारा..(व्यवधान).. हो गया है? आप किस बात पर बोल रहे हैं? ..(व्यवधान)..आप महिला सुरक्षा के लिए क्या कहते हैं? ..(व्यवधान)..महिलाओं के लिए..(व्यवधान)..क्या करते हैं? ..(व्यवधान)..आप आंकड़े देते जाते

हैं..(व्यवधान)..आंकड़े दिखाते हैं। ..(व्यवधान)..महोदय, इन आंकड़ों से कुछ नहीं होगा। ..(व्यवधान)..आपका इरादा होना चाहिए।..(व्यवधान)..महिलाओं की मर्यादा होनी चाहिए। ..(व्यवधान)..अगर आप यह नहीं दे सकते हैं, तो * से इस बजट का ड्रामा मत कीजिए। ..(व्यवधान).. (समाप्त)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : माननीय सदस्या ने माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए जो बात बोली है ..(व्यवधान)..वह unparliamentary है। ..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : जो अनपार्लियामेंटरी शब्द हैं, मैं उन्हें निकाल दूंगा। ..(व्यवधान)..

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : उनके लिए जिस तरह की भाषा बोली गई है, उसको expunge किया जाए।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : expunge किया जाएगा। श्री तिरुचि शिवा, आप बोलिए।

श्रीमती रेणुका चौधरी : उपसभापति जी..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : देखिए, आप बैठिए।..(व्यवधान).. I will remove. I will expunge that thing from the topic. ...(Interruptions)..

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : ये किस तरह की भाषा बोल रही हैं? ..(व्यवधान)..अगर इनको आईना दिखाया जाएगा..(व्यवधान)..तो उस आईने में..(व्यवधान)..अगर आपकी कांग्रेस का..(व्यवधान)..है तो हम क्या कर सकते हैं?..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : श्री तिरुची शिवा जी, आप बोलिए।

(klg/2m पर आगे)

KR/KLG/2M/5.05

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): You sit down. ..(Interruptions).. If it is unparliamentary, it will be removed. ..(Interruptions).. Sit down. If it is unparliamentary, it will be removed. ..(Interruptions).. Sit down. देखिए, आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : महोदय, ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है।... (व्यवधान)... किस तरीके से ये बोल रहे हैं। अगर इनको आईना दिखाया जाएगा, तो उस आईने में ...(व्यवधान)... तो हम क्या कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am happy and proud to participate in this debate as a representative of the DMK Party which has been a pioneer in social justice. Not only that, we have been a forerunner in implementing the social welfare schemes, first ever in the country which has been taken as a cue by the Union Government in this Budget. Sir, the Health Insurance Scheme, the Maternity Benefit Scheme, the Farmers' Market, the LPG connections to the poor have all been implemented first ever in Tamil Nadu. So also in the Budget, the Government has assured that in the year 2022, whole of India and the rural parts will be electrified. Sir, way back in 1972 itself, 50 years before when our leader, Dr. Kalaignar was the Chief Minister, all the rural villages in Tamil Nadu had been electrified. So, Sir, I am very happy that we have been pioneer and forerunner in implementing the welfare schemes. The second is we are also happy that regional parties have become the guiding force to the national parties whenever they brought such schemes.

Sir, I would like to thank the Finance Minister on this occasion, before going to the bitter part of my speech, that he has reduced the GST for the food products in the hotels from 18 per cent to 5 per cent, which has been represented by us, and he has agreed to that. We are thankful to him for

that. So also, he has exempted tractors from commercial vehicles and retained them as agricultural part. The third is, Sir, today, we have received a letter from the Finance Minister that the proposal for borewells, which are used for the irrigation purposes, to be exempted from the GST, is to be placed before the GST Council which is to sit next time.

I come to the main part of the Budget Speech. The Economic Survey has stated that the major part of our economy is decided by the informal sector, that is, 87 per cent. Out of the 87 per cent, only 12 per cent of the firms are registered under the GST but do not provide social security. Less than 0.1 per cent provide social security but are not registered under the GST. Sir, the Government when it assured that the workforce in the formal sector will be given adequate benefits, equal to the informal sector, I would like to say that because of demonetization the social security scheme in the informal sector has suffered a lot. Sir, in the Budget, the Finance Minister has said, time and again, that the demonetization has done good for the country. Yesterday, my good colleague, Shri Bhupender Yadav, also said that they have shelled out the black money. It is very surprising. Sir, I would like to say that when demonetization was announced on 16th November, 2016, the total amount of SBN, that is, Specified Bank Notes, of Rs.1000 and Rs.500

denominations was valued at Rs.15.4 lakh crore, that is, 86.9 per cent of the total value of the currency in the circulation. Later the Annual Report of the RBI stated that subject to future corrections based on verification process when completed, the estimated value of SBN, Specified Bank Notes received as on 30th June, 2017, that is, within six months after the demonetization was announced, Rs.15.28 lakh crore, which constitutes 98.96 per cent of the currency.

(Continued by 2N/KS)

KS/2N/5.10

SHRI TIRUCHI SIVA (contd.): So, twelve lakh worth of currency has not come into the mainstream. I have little knowledge about it. I would like the Government to clarify and enlighten me from where it has shelled out the black money. If the total amount of money in circulation was only 15.4 lakh crores of rupees, and the money that has been deposited back is Rs.15.28 lakh crores, from where does this black money come? Nothing has been shown. So is the case with the fake currency. The fake currency was supposed to be only forty-three...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Sivaji, your five minutes are over. I request you to conclude.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, we have been waiting. One or two Members from the 'Others' category are not present. I just want a little time more.

Our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, had already speculated and stated that the GDP growth rate would decline by two per cent. It was very vivid and clear in the 4th quarter of 2016-17, when the GDP had declined from 7% to 6.1%. Also, unemployment would be increasing.

Sir, the third very important issue is the condition of our agriculture. The Government has assured that in the year 2022 the income of farmers would double, and that the MSP would be 150 % more or so. But, first, I would like to ask whether it is an Annual Plan or a Five-Year Plan. The Budget is considered to be an Annual Plan. But all those announcements are about a further period of not just one or two years, but about a period of five years. Sir, let me say that we should not basically forget that India is an agricultural country. And agricultural land has been declining year after year. We should also recollect that during the economic recession, which started from US and spread to the whole of Europe, India had not been affected, and this was mainly for two reasons. One was that the agricultural sector was sound; we were not in food deficit; the second was the public sector undertakings. And now you do not care for both these things! If, at all, you

say that fiscal deficit has been brought under control, it is mainly because of, one, the slide in oil prices and, two, by way of disinvestment of even profit-making PSUs. Sir, steel plants are making profits. BHEL is making profit. They are all in Navaratna and Maharatna categories. But they are all being disinvested. One can understand if you are disinvesting some loss-making PSUs; but you are disinvesting even profit making PSUs, and with that money, you are balancing fiscal deficit and saying that you are capable of running the Government with some economic wisdom. No, Sir! I am very sorry to say, Sir, that statistics show that agricultural land has been reduced by 3.16 million hectares. Agricultural land has been diverted from 'agricultural use' to 'non-agricultural use'.

Sir, population has been increasing. Food requirement has been increasing. But agricultural land has been decreasing. Farmers are on the streets. When they were there at the Jantar Mantar, no one took care of them. They have been committing suicides; no one is taking care of them. During the demonetisation period, people died at the gates of banks; pensioners suffered without getting money from the banks; women who had saved some money without the knowledge of their men at homes, suffered. So, the farmers are not being taken care of, but, still, you are assuring that

they would be safe! When agricultural land has been shrinking, when farmers are on the streets, and when they are committing suicides, how are you going to save the agricultural sector in this country? It is the largest employment-provider.

Now, some announcements have been made in the Budget...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Please conclude in one minute.

SHRI TIRUCHI SIVA: I would just conclude. What are the allocations? What is the increase and what is the decrease? The decrease is very much to be seen and felt, and the increase is not sufficient when compared to the required level.

Let me talk about the rural electrification scheme. What is that Pradhan Mantri...? I don't know because it is in Hindi. The amount allotted is Rs. 3,500 crores, whereas the amount that should have been allocated should have been Rs. 8,720 crores; so, it is 59 per cent less than what was required.

KGG-SCH/2O/5.15

SHRI TIRUCHI SIVA (contd.): So also on the Scheduled Castes Sub-Plan, it was recommended that Rs.86,796 crore be allocated but only Rs.56,719 crore has been allocated. I should say that only by looking at the announcements made by the Finance Minister and his statistics, one may assume that a little increase of money has been there but it is not to the required level.

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : धन्यवाद, शिवा जी, आपके 10 मिनट हो गए हैं। I have given you double the time. Please conclude. I will have to call other names also.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, kindly extend the time. If you insist, I am prepared to sit down right now. ...(Interruptions)... Kindly permit me to speak for a few more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Kindly conclude in two minutes.

SHRI TIRUCHI SIVA: The demand of the Ministry of Human Resource Development was Rs.55,000 crore. The amount allocated is Rs.26,129 crore. Already there are nine lakh vacancies of teachers across the country. HRD is the most important portfolio of the Department in this country. It had

demanded for Rs.55,000 crore and the allocated money was 52 per cent less than the amount that should have been allocated. Sir, these are the issues that we have to focus. On these issues, you have to consider very seriously. The Budget which is being focused as pro-poor is not so. All those welfare schemes which you have given in the Budget, I would say that there are too many promises but there is not even a smallest, single guarantee as to how they would be implemented. What are the resources? How will it be done? They are only announcements on paper. At the very beginning itself I had said that we wanted to appreciate. But demonetization has not benefited the country; the GST has taken the country to a very bad level. So many sectors are suffering because of shortcomings in the GST implementation. The Council is sitting again and again to reconsider GST rates. Above all these things, the agricultural sector is neglected, the educational sector is neglected, the employment issue has not been tackled to the level it should have been tackled, but the Government says that one who is wearing a *hawai chappal* too can fly in the aircraft. But I am sorry to say that he may even fly with a *hawai chappal*, but he will not be able to fly with a bare body and an empty stomach.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Now Dr. Vikas Mahatme...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी का रिप्लाई 5.00 बजे होना था और हम लोगों की 7.00 बजे की फ्लाइट है। या तो आप पहले वाली परम्परा को फॉलो कीजिए कि सब लोग बोल लें और रिप्लाई न हो, ताकि हम लोग भी जाएं। अगर रिप्लाई होना है, तो कितने बजे होना है? आज लास्ट डे है, लोक सभा एड्जर्न हो चुकी है, आप यहां बैठे हैं और हाउस को 10.00 बजे तक चलाने के मूड में हैं। हम लोग कोई 10.00 बजे तक थोड़े ही बैठे रहेंगे। हमें अपने क्षेत्र में वापस जाना है। हम परमानेंट राज्य सभा वाले नहीं हैं, हमें अपने-अपने क्षेत्रों में वापस जाना होता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका जवाब दें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : महोदय, सदन सदस्यों की राय से चलता है और आज यही राय बनी थी कि तीन घंटे में हम इस चर्चा को समाप्त कर लेंगे, इसलिए मेरी पार्टी की तरफ से हमने चार वक्ताओं के नाम विद्ड्रॉ कर लिए थे, क्योंकि मुख्य वक्ता के माध्यम से सारी बातें आ जाती हैं। अगर दूसरी पार्टीज़ भी ऐसा कर सकें और खास तौर से मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन करूंगा कि अगर वे ऐसा कर सकें, तो कर लें और अगर नहीं कर सकें, तो अपनी बात को थोड़े शब्दों के अंदर रखें, ऐसा मेरा अनुरोध है। ऐसे में वित्त मंत्री जी जल्दी जवाब दे पाएंगे।...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : आप वित्त मंत्री का रिप्लाई करवाइए, क्योंकि बातें तो वही रिपीट हो रही हैं।

श्री विजय गोयल : यह बात आप उधर समझाइए न।...(व्यवधान)...

श्री भूपेन्द्र यादव : उपसभाध्यक्ष जी, आप समय तय कीजिए।...(व्यवधान)... सब मेम्बर्स के लिए निश्चित समय तय होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Why are they insulting by asking us not to speak? ...(Interruptions)...

श्री प्रमोद तिवारी : उपसभाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री रिपुन बोरा : यह सही बात नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री विजय गोयल : प्रमोद जी, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं।...(व्यवधान)... एक मिनट के लिए आप बैठिए।...(व्यवधान)... प्रमोद जी, एक मिनट बैठिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : आनंद भास्कर रापोलू जी, वे बोल रहे हैं, अभी आप बैठिए।...(व्यवधान)... आप भी नाम आएगा।

(2p-rpm पर जारी)

RPM-KLS/2P/5.20

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन सदस्यों के लिए है। जैसी आपकी राय बनेगी, वैसा करेंगे। अगर वित्त मंत्री सायंकाल 6.00 बजे जवाब दें, तो इसके लिए आप सब लोग एग्री करें, तभी ऐसा हो सकता है और उसी के हिसाब से समय का आवंटन कर लें, क्योंकि इसमें सभी सदस्यों का सहयोग चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारीः माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और वरिष्ठ वक्ता रह गए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी insist करती है कि हम बोलेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : आप लोग बोलिए, लेकिन जितना टाइम दिया है, उतने टाइम में बोलिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारीः माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति पूरा आदर व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि जितने टाइम में और लोग बोले हैं और जितना टाइम आपने और सभी माननीय सदस्यों को दिया है, उसी रेश्यो में हमारे वक्ता भी टाइम लेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल)ः डा. विकास महात्मे।

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र) : महोदय, यह बजट मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि इस बार के बजट में सारे भारतवासियों को भरोसा और विश्वास हुआ है कि अब भारत आगे बढ़ सकता है। थोड़े ही सालों में भारत एक विकसित देश बनने वाला है। चूंकि मैं डाक्टर हूं और मेडिकल फेकल्टी से आता हूं, इसलिए मैं ज्यादातर 'आयुष्मान भारत' के बारे में बताना चाहूंगा।

महोदय, 'आयुष्मान भारत' पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी सबसे बड़ी स्कीम है, जिसके माध्यम से देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है। अमेरिका में जैसे 'ओबामा केयर " को जाना जाता है, वैसे ही मुझे लगता है कि यह योजना सोशल मीडिया पर 'नमो केयर' कर के जानी जा रही है। इसी प्रकार से आगे भी इसकी पहचान होगी। मैं बताना चाहता हूं कि इस पर विपक्ष ने काफी सवाल उठाए थे। श्री जयराम

रमेश जी का इसके बारे में कहना था कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर होना चाहिए न कि केवल 50 करोड़ लोगों को ही इसका लाभ मिले। मुझे भी लगता है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत तो कुछ लोगों से ही हो सकती है। जैसे अभी 50 करोड़ लोगों से इसकी शुरुआत हो रही है, वैसे ही बचे हुए 70 करोड़ लोगों को हम कुछ ही साल में यह सुविधा दे पाएंगे। इस प्रकार देखें, तो इस देश में यूनिवर्सल हेल्थ केयर लाने के बारे में इस सरकार ने और हमने सबसे पहले कदम उठाया है।

महोदय, जैसा कहा गया कि इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर की भी आवश्यकता है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन मैं आपके जरिए सदन और देशवासियों को बताना चाहूंगा कि यह सरकार देश में लगभग डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर्स खोल रही है। इससे मुझे लगता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर भी उसमें आने वाली है। इन वेलनैस हेल्थ सेंटर्स के जरिए हम प्राइमरी हेल्थ केयर का समाधान पूरी तरह से करेंगे। इस प्रकार से इन सेंटर्स के जरिए हम प्राइमरी हेल्थ केयर के साधन जनता तक पहुंचाएंगे।

महोदय, देश के लोगों और विपक्ष को भी लग रहा है कि इस योजना से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा होगा। मुझे भी इसका डर है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश में गवर्नमेंट की चार इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो ये इंश्योरेंस ले सकती हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे भारत में कर सकती हैं। इसलिए मेरा कहना है कि यदि इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन सरकार की इन चार कंपनियों के माध्यम से होता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। यह परेशानी शायद अमेरिका में हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष में नहीं होगी।

महोदय, काफी लोगों का यह सवाल भी था कि इस योजना से प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स को लाभ होगा, लेकिन मुझे बताइए कि प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स के बगैर, भारत में हेल्थ के बारे में एक भी स्कीम को सक्सेफुल तरीके से नहीं चला सकते हैं, क्योंकि भारत में आज जो भी डाक्टर्स हैं, उनमें से 80 प्रतिशत डाक्टर्स प्राइवेट हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। देश में जो भी हेल्थ सर्विसेस प्रोवाइड होती हैं, वे केवल 20 प्रतिशत ही सरकारी क्षेत्र में दी जाती हैं, बाकी प्राइवेट क्षेत्र में दी जाती हैं। इस प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि हम जो काम 70 साल में नहीं कर सके, वह एक ही साल में नहीं हो पाएगा, इसलिए प्राइवेट डाक्टर्स की हैल्प लेना बहुत ही जरूरी है।

महोदय, श्री जयराम रमेश जी ने यह भी कहा था कि out of pocket expenses का क्या होगा और वे काफी ज्यादा होते हैं ? मैं भी उनसे सहमत हूं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि out of pocket expenses दवाओं और investigations पर ज्यादा होता है। Out of pocket expenses जो दवाओं पर खर्चा होता है, उसके लिए सरकार की तरफ से जन-औषधि योजना बाजार में लाई गई है। उससे आज 70 से 80 प्रतिशत दवाओं की कीमत कम हो गई है और मुझे लगता है कि उससे out of pocket expenses कम हो जाएंगे।

(2 क्यू/पीएसवी पर जारी)

PSV-SSS/2Q/5.25

डा. विकास महात्मे (क्रमागत): वैसे ही इन्वेस्टिगेशंस तभी ज्यादा होते हैं, जब मरीज भर्ती होता है। इसके लिए जो भी टॉप अप या खर्चा लगता है, वह स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और एक अच्छी बात जो है, मुझे लगता है कि हम इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। वह यह है कि हमें पता है कि भारतवर्ष में सभी डॉक्टर्स माने जाते हैं, world over माने जाते हैं और बाहर के देशों से भी बहुत सारे लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारतवर्ष में आते हैं। वैसे ही नर्सेज़ की बहुत डिमांड है। ...(समय की घंटी)... बाहर के देशों में भी भारतीय नर्सेज़ की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अभी जब इतनी बड़ी स्कीम 'आयुष्मान भारत' आयेगी, 'नमो केयर' आयेगी, तो काफी मात्रा में पैरा मेडिकल्स लगेंगे। हम स्किल सेंटर्स के जरिए ये पैरा मेडिकल्स भी बहुत अच्छे से तैयार कर पायेंगे। यह बहुत जरूरी है कि हमारे जो 10वीं-12वीं पास लड़के हैं, youths हैं, उनको हम इसमें समाविष्ट कर लेंगे और इसमें उनको जॉब्स की अपॉर्च्युनिटी है। मुझे लगता है कि हेल्थ केयर में इनके जरिए सब लोगों तक, 50 करोड़ लोगों तक पहुँचने के लिए, एक जो जॉब का प्रश्न है, यह उसे अपने आप ही हल करने वाली स्कीम होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है कि हम इसे जान लें। काफी बार यह कहा जाता है कि यह जो बात है, यह भी एक जुमला है, क्योंकि इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। ...(व्यवधान)... लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके पहले कांग्रेस का भी एक नारा था- 'गरीबी हटाओ'। क्या वह जुमला नहीं था? क्या आज तक गरीबी हटाई गयी है? उन्होंने इलेक्शन के वक्त उस जुमले का कई बार

उपयोग भी किया है। मुझे लगता है कि इसे जुमला नहीं कहा जाए, क्योंकि यह जो 'नमो केयर' है, यह भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यह भारतवासियों के लिए अच्छा रहेगा और गाँवों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। ...(समय की घंटी)... वैसे ही जब हम गाँव की मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी सोचना चाहिए और पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा आवंटन किया गया है। जैसे इसके पहले भी अटल जी की सरकार में 'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना ' से काफी लाभ हुआ था, वैसे ही माननीय नितिन गडकरी जी के जरिए गाँव को शहर से जोड़ने का काम बहुत अच्छे ढंग से हो पायेगा। मैं सभी को यह बताना चाहूँगा कि नितिन गडकरी के यहाँ उन्होंने एक पोस्टर लगाया है, जिसमें यह लिखा है कि ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): श्री महात्मे जी, समाप्त कीजिए।

DR. VIKAS MAHATME: "American roads are good not because America is rich. But America is rich because American roads are good." So, we need good roads in villages also. इसके जरिए जो भी अनाज है, उसे मार्केट तक पहुँचाने के लिए यहाँ रोड्स बहुत जरूरी हैं और यहाँ के रोड्स की वजह से रोजगार भी उपलब्ध हो सकता है। मुझे यह लगता है कि असंगठित क्षेत्र में रोड्स के लिए लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वैसे ही बहुत जरूरी है कि आईटी सेक्टर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। ...(समय की घंटी)... मुझे यदि एक किलो चावल फ्लिपकार्ट या एमेज़ॉन के जरिए ऑनलाइन परचेज़ करना है, तो मैं यह बताना चाहूँगा कि वह कितने दिन में कहाँ

आयेगा, कितने बजे मेरे घर पहुँचेगा, यह सब मुझे पता चलता है और कौन से गोडाउन से निकलेगा, कौन सी गाड़ी से आयेगा, यह भी मैं ऑनलाइन देख सकता हूँ। लेकिन आज यदि किसान को अपना अनाज बेचना है, तो उसके लिए यह बहुत मुश्किल है कि मार्केट कहाँ है, वहाँ तक वह कैसे पहुँचाए और कहाँ वह गोदाम में रखे। तो यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम जो रोबस्ट आईटी फ्रेमवर्क उनको दे रहे हैं, हम साथ में सॉफ्टवेयर्स भी देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब मार्केट में कठिनाई नहीं होगी और हम जो उनकी आय दोगुनी करना चाहते हैं, उसके लिए यह बहुत बड़ा कदम है। ...(समय की घंटी)...

मुझे पता है कि समय की बहुत कमी है। काफी मुद्दे हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो बजट है, यह सभी भारतवासियों का हौसला बढ़ाने वाला है। हम नये भारत, नयी दिशा के लिए जा रहे हैं और हम एक नये भारत का निर्माण करेंगे, ऐसा विश्वास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ, धन्यवाद।

(समाप्त)

(2आर/एनकेआर पर आगे)

NKR-NBR/2R/5.30

श्री राज बब्बर (उत्तराखंड) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर होने वाली महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का समय दिया। सारे सदन की भावना सुनने के बाद, मुझे लगा कि हमारे विद्वान साथियों ने लगभग

सभी बिन्दुओं को सदन में रख दिया है। इसलिए मैं अपनी बात को सिर्फ दो ही विषयों तक सीमित रखूंगा और बहुत ज्यादा गम्भीर बातें करने की बजाए सिर्फ हल्की-सी बात ही करूंगा।

बजट में आई गिनतियों पर यहां काफी चर्चा हुई और गिनतियां बताई गईं। मैं गिनतियों से ही आरम्भ करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह बजट आम जनता के साथ एक खूबसूरत छलावा है। यह बजट देश के अरबों देशवासियों के लिए नहीं है, बल्कि अरबपतियों के लिए है। इससे देश के जनमानस को आंकड़ों के हेरफेर में उलझाया जा रहा है। इस बिन्दु पर चर्चा करने से पहले, मैं कहना चाहता हूं कि - 'सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि :, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम '। चाणक्य ने कहा है कि सत्य से भागने से कुछ नहीं होगा। सत्य ही पृथ्वी को संतुलित रखता है।

महोदय, 2014 में चुनाव से पहले आंकड़ों और data की भाषा नहीं बोली जाती थी। आपने 450 से ज्यादा मीटिंग्स की होंगी और जो शब्द बार-बार बोले जाते थे, वे थे - jobs, बेरोज़गारी, यूथ, हर साल 2 करोड़ बेरोज़गारों को नौकरियां, किसानों की बदहाली, सेना के जवानों की शहादत का बदला, काला धन, हर नागरिक के account में 15 लाख रुपए आदि-आदि।

महोदय, इस बजट में चार बार गिनने के बाद, समझ में आया कि कुल 18,000 शब्द हैं और इन 18,000 शब्दों में job शब्द सिर्फ 6 बार आया है। इससे आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए

कितना संजीदा मौजूदा बजट है। मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, हमारे सभी साथियों ने, सभी विद्वानों ने इन्हें समझाने की कोशिश की है - अगर समझ में आ जाए तो। एक यूथ शब्द है, जिसे इन्होंने लाइन में लगा दिया। यूथ शब्द पूरे बजट में सिर्फ तीन बार आया है। रोज़गार के अवसरों के लिए कोई नया विचार नहीं है, सिर्फ स्टार्टअप्स, स्टैंडअप्स हैं - जिनकी सफलता संदिग्ध है। आप 55 सालों की कांग्रेस की सरकार की स्थिति की बात करना छोड़ दें, सिर्फ उनकी चर्चा करें, जो वायदे आपने जनता से किए थे। आपने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी। डिटेल आपको बता दी गई है। अब EPF का data गिनाया जा रहा है। जान-बूझकर उलझाए हुए आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। अपनी ही सरकार की लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़े आप देख लीजिए, जो चिल्ला-चिल्लाकर कहते हैं कि पिछले चार सालों में जहां 8 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थीं, वहां मात्र 4-5 लाख नौकरियां मिली हैं। हालात सुधर सकें, इसके लिए बजट में कोई नई योजना नहीं है।

(उपसभाध्यक्ष, श्री तिरुची शिवा पीठासीन हुए)

आदमी को जीवनयापन करने के लिए, जिन्दा रहने के लिए, खाने के लिए data नहीं आटा चाहिए। बेरोज़गार नौजवान, जिसकी परिभाषा हमारे एक आदरणीय साथी ने दी है, jobs का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देश के बेरोज़गार नौजवान को regular रोज़गार चाहिए लेकिन यहां से regular भाषण मिलता है। ..(व्यवधान)..

महोदय, दुर्भाग्य है कि इस देश के नौजवानों को नफरत की अफीम पिलाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस हकीकत से ये वाकिफ न हों। ये अच्छी तरह, भली-भांति

परिचित हैं और जानते हैं, लेकिन अपनी असफलता, गवर्नेंस की चुनौतियों से भागते हुए नौकरी नहीं दे पाने की वजह से, ये उसकी भरपाई करते हैं और नौजवानों के हाथ में डंडे देते हैं।

(2S/DS द्वारा जारी)

DS-USY/5.35/2S

श्री राज बब्बर (क्रमागत) : कल हमारे साथी ने बोला कि बाँस फाइबर में आता है। इनके लिए वह फाइबर में नहीं आता है, डंडों के लिए आता है, इसलिए उसमें छूट देकर उसे घास में लाने का काम किया है। आपकी बातों में आकर युवा आज की तारीख में न तो समाज के काम आ रहा है और न ही अपने परिवार के काम आ रहा है। वह सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो चुका है। यूपी के कासगंज के चंदन की मौत की वजह ही यही है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस दिन झण्डारोहण हो और झण्डा फहराने की बहस के अंदर नौजवान की जान चली जाए, इसके सवालों के जवाब इनको देना होगा। इसका कारण यह है कि नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वह एक आक्रोश में निकला हुआ है। महोदय, नौजवानों के बारे में बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में कह दिया गया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूँगा।

महोदय, अब रहा किसान, तो किसान को भी इन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्ष 2014 में इनका घोषणा पत्र निकला था, जिसके पन्ना नम्बर-44 के ऊपर इन्होंने उस वक्त किसान की लागत का डेढ़ गुना देने

का वादा किया था। चार साल बीत जाने के बाद, अब इनको किसानों की याद आई है। वह भी न आती, लेकिन गुजरात का चुनाव और राजस्थान के उप-चुनाव के अंदर जब किसान की नाराजगी खुल कर वोटों के रूप में सामने आई, तब बात इनकी समझ में आई। यही वजह है कि इन्होंने इस बार अपने बजट में फार्मर का नाम, किसान का नाम 30 बार लिया है। शायद यही वजह हो सकती है कि 18,000 शब्दों वाले बजट में इन्होंने 30 बार किसान का नाम लिया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) : पिछली बार रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ...(व्यवधान)...

श्री राज बब्बर : आप पढ़ लेते, तो शायद समझ में आ जाता कि तब भी कुछ नहीं दिया और आज भी कुछ नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... किसान भोला जरूर है...(व्यवधान)... हमने बहुत समझाया...(व्यवधान)... किसान भोला जरूर है, लेकिन...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Raj Babbarji, please conclude.

श्री राज बब्बर : सर, अगर आप कहेंगे, तो मैं बैठ जाऊँगा। लेकिन, मुझे केवल दो प्वाइंट कहने हैं, मैं उनको कहूँगा और बैठ जाऊँगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा। मैंने खुद ही अपना सब कुछ कम कर दिया है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। ...(व्यवधान)... मगर, किसान से समझदार कोई दूसरी कौम हमारे देश में नहीं है। उसे बताने की जरूरत नहीं है, वह समझ गया है कि यह आँकड़ों की बाजीगरी है और बहुत सारे साथी उनके

यहाँ भी समझते हैं कि जब वे अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि आखिर ये आँकड़ों की बाजीगरी का मुकाबला कैसे करेंगे? अगर ईमानदारी होती, तो बजट में किसान की लागत को तय करने का जो फॉर्मूला है, उसमें ये बदलाव नहीं करते। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। लागत में बीज, खाद, फैमिली लेबर को तो शामिल रखा है, लेकिन....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Raj Babbar*ji*, four more Members have to speak. Kindly make it fast.

श्री राज बब्बर : लेकिन, जमीन के रेंट के बारे में कोई बात नहीं की है। जमीन का रेंट नहीं है। क्या किसान बिना खेत के खेती करेगा? किसान के पास अगर जमीन नहीं होगी, तो वह खेती किसमें करेगा? इन लोगों ने फैमिली लेबर को तो include किया है, लेकिन किसान को झांसा देना, वह आपकी फसल बीमा योजना में पहले ही बहुत झांसे खा चुका है। उस बेचारे को इतना झांसा मिला कि उसकी रकम, उसके पैसे उसके एकाउंट में से अपने आप फसल बीमा के लिए कटते गए, लेकिन उसको वह नहीं मिला।

...(समय की घंटी)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude.

श्री राज बब्बर : मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जहाँ से 73 सांसद आते हैं और मुझे खुशी होगी कि उन सांसदों के बीच मैं एक बार तीन सवाल करना चाहता हूँ। उनकी जानिब से कि इस सरकार ने अपना ही वादा पूरा करने में चार साल क्यों लगाए हैं, क्या वह इसका जवाब किसान को देगी? उन चार सालों में आपका दिया हुआ वादा लागू करने

की वजह से किसान को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई उसको मिलेगी? तीसरा, इन चार सालों में कम से कम, जो लोगों का अनुमान है और जो साथियों ने बताया है कि अगर उनको लागू कर दिया गया होता, तो किसानों की जेब में 1 लाख करोड़ रुपये जाते।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude, Raj Babbar*ji.*

(2टी/पीके-एमसीएम पर आगे)

PK-MCM/2T/5.40

श्री राज बब्बर : इन बातों का जवाब अपनी बजट स्पीच में देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। महोदय, वैसे तो जुमलेबाजी की जुगलबंदी है यहां। प्रधान मंत्री कोई जुमला कसते हैं, अध्यक्ष महोदय बताते हैं कि वह 15 लाख वाली बातजुमला था। अभी यहां आए तो प्रधान मंत्री जी इम्प्लीमेंटेशन जी0एस0टी0 के लिए कुछ फाल्टी बता रहे हैं और यहां अध्यक्ष जी आकर कह रहे हैं कि लाज़वाब जी0एस0टी0 है, कमाल की जी0एस0टी0 है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Kindly conclude please.

श्री राज बब्बर : सब कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं भी कहता हूं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन यह तो ये लोग भी मानेंगे कि अटल जी से बेहतर नहीं बोलते। अगर मैं गलत कह रहा हूं और अगर आपको लगता है कि अटल जी से बेहतर बोलते हैं तो बता दीजिए, मुझे टोक दीजिएगा। मैं यह मानता हूं कि अटल जी से बेहतर नहीं बोलते।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): There are four more speakers from your party. Please conclude.

श्री राज बब्बर : अटल जी की सरकार 2004 के अंदर थी। फिर यू0पी0ए0 की सरकार आई और इसलिए इस बार इस बात को ध्यान रख लें कि बोलने से सरकारें नहीं बनतीं और चलने से पहले एक बार कह देता हूं,

"कैसी मशाल लेके चली तीरगी में आप,
जो रोशनी थी, वो भी सलामत न रही।"

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you very much. Now, Shri V. Vijayasai Reddy. I hope you will stick to the time limit.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (ANDHRA PRADESH): Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of my party, YSR Congress Party, and my Party President, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, I thank you for having given me the opportunity. Sir, there is a great amount of injustice that has been meted out to the State of Andhra Pradesh in this Budget and also in the commitments that had been made in the Reorganisation Act. The first and the foremost thing is the Special Category Status which had been assured by none other than the then Prime Minister of this country, in 2014. Sir, I would like to bring to your notice that the Special Category Status for the

Residuary State of Andhra Pradesh is a lifeline and there cannot be any substitute for the Special Category Status. A special package is no alternative for Special Category Status. Therefore, unless and until Special Category Status is granted to the Residuary State of Andhra Pradesh, it can't develop equally with the other States. It has already been left as agrarian State, and, in future also it will continue to be an agrarian State, if Special Category Status is not granted.

Sir, the next point is railway zone. There, the Railway Minister, yesterday or day-before-yesterday came to the floor, and, then, misled the House. I have no hesitation in saying that the Railway Minister has misled the House. The Act does not contemplate consultation with the other parties. The Act has, specifically, provided that a railway zone would be created/constituted. When the Act is so specific, why is the Government delaying constitution of a separate railway zone? Now, the Railway Minister says that he has to consult the other States and he has also to consult the other stakeholders. Why is it? So, that is one of the provisions that has been incorporated and that has to be implemented. The Integrated Steel Plant at Kadappa, a port at Dugarajapatnam, Vizag Petrochemical Complex, Vizag Chennai Industrial Corridor and Metro Rail at Visakhapatnam and

Vijayawada --- these are all important issues. Apart from this, in Schedule XIII, there is a list of 11 Central institutions, out of which 9 have been established only in temporary premises and adequate allocations in the last four Budgets have not been made. Therefore, I request the Government of India to address this issue. (Time-bell) Sir, how many minutes left now?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You have two more minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I will address only two important issues. First is farmers' distress.

(Contd. by PB/2U)

PB-SC/2U/5.45

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): Sir, agriculture accounts for 16 per cent of India's GDP, and 49 per cent of India's employment comes from the agricultural activities. Sir, the National Sample Survey, 2013 Report shows that 51.9 per cent of the farm households in India are indebted. So, this indebtedness by the farmers is to be addressed by the Government of India. Insofar as Minimum Support Price is concerned, many Members have spoken about that. I will only say one thing. The Finance Minister while presenting the Budget of 2017 had categorically stated that he will ensure

that the farmers' income would be doubled in next five years by 2022. Therefore, if at all this is addressed and this can be accomplished, the farmers across the country would be delighted and they will remember the Ruling Party — whichever Party does it — forever.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: One more minute. Sir, I am not touching upon the Minimum Support Price. It is only the cost of production. What is the cost? Even the Finance Minister, when he stated in his Budget Speech that he is increasing the Minimum Support Price by 150 per cent of the cost, has not defined what is that cost. I want to know whether it is A2 or A2+FL or C2. What is that? That has to be spelt out by the hon. Finance Minister.

Sir, there are last two issues which are very important issues.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): How many last issues?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Two issues.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCH SIVA): Please conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, one is about the farmer producer companies. To the best of my knowledge, any income from agriculture is exempted from the tax under Section 2, Sub-section (1) of the Income Tax Act. It is undoubtedly a happy thing that the Finance Minister has pointed

out that a number of farmer producer companies have been set up in India and these companies are basically set up by the group of farmers. Now whether they constitute partnership firm or company or they do it individually, it doesn't make any difference. Agricultural income is an agricultural income which is exempted from tax. ...(Time-bell)... Sir, the Finance Minister has exempted this income by these farming companies with a rider, with a sunset clause in the proposal. Why is this sunset clause? The sunset clause says that the income of the farmer producer companies is exempted only for a period of five years. Why five years? When agricultural income is totally exempted from the tax, why five years' tax holiday with a sunset clause? Therefore, I hope the Finance Minister will positively consider exempting it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: One more point, Sir.

Secondly, even these farmer companies have to pay dividend distribution tax which is totally unreasonable and unwarranted for India's condition.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Yes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: One last point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): How many last points? ...(Interruptions)... Please conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: This is very important. Sir, the CAG Report, the Comptroller and Auditor General Report, on Government accounting found that the Government has deferred the payments amounting to more than Rs. 1.87 lakh crores in 2015-16. I request the hon. Finance Minister to address this issue.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you Mr. Vijayasai Reddy. Now Prof. Rajeev Gowda.

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (KARNATAKA): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir.

Sir, I want to actually start my speech on the Budget by congratulating the Government and the Finance Minister on funding Suburban Rail Service for Bangalore City. This is something that the Karnataka Government has been very proactive about. As an activist, I have been fighting for this for many years. Across party lines, we are in unity in terms of support for the suburban rail. It will go a long way in clearing the traffic challenges that Bangalore city faces. ...(Interruptions)...

I also want to congratulate the Government for adopting many of the innovative programmes set up by the Government of Karnataka under Shri Siddaramaiah. In this Budget announcement, there were multiple such examples. For example, the Electronic National Agricultural Market place is a national application of our *Rashtriya* e-market place. The Programme to lend and rent out farmer equipment is the national equivalent of the *Krishi Yantra Yojana* of Karnataka Government.

(Contd. by 2w/SKC)

SKC/2W/5.50

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (contd.): The solar pumps initiative is a replica of the *Surya Raitha* programme of the Karnataka Government, and the programme for pregnant and lactating women is a national application of the very successful and impactful *Mathru Purna* Scheme, which would go a long way in addressing the health of women and children and in addressing issues of low birth rate, and bring down infant mortality, maternal mortality, stunting, etc.

Sir, after complimenting the Government, let me now focus on points where I need to show where the Budget and this Government is falling short of our expectations of any good governance. First of all, there is an

extraordinarily excessive reliance on cesses. The real problem with this is, a cess is supposed to be earmarked for a particular purpose, but already we have seen, in recent times, that the Coal Cess that was supposed to go to the National Clean Energy Fund instead is being used to compensate States for GST losses. What is the logic for that and how can you say that this is a cess that was targeted for a particular reason when you are directing it somewhere else? The problem with cesses is that like indirect taxes they are regressive, and they hurt the poor more than they hurt the rich.

Sir, the total cess collection from this Government is expected to be three lakh crore rupees. Compare that with the capital expenditure for the financial year, 2018-19, which is also three lakh crore rupees. It appears as if this Government is not going to raise revenues other than through such iniquitous methods such as cesses. This brings me to the education cess. Here again there is going to be uncertainty on how much is actually going to be raised and, in States, you find that cesses are being allocated for all these fundings for programmes which absolutely need targeted revenue allocated to them.

Sir, I am also outraged by one move of this Finance Minister, where he has played a game, a sleight of hand, on the front of petrol and diesel excise

duties. When the Centre collects Excise Duty on petrol and diesel, it becomes part of the divisible pool and 42 per cent goes to States. What has this Government done? It has cut Excise Duty by six rupees per litre with an additional two rupees per litre-cut on excise on diesel and petrol, and to balance this cut and to ensure that the Centre's revenues do not come down, they have imposed an eight rupees per litre Road and Infrastructure Cess. As I mentioned, the cess monies will go only to the Central Government and the States are shafted. Now, how much is this loss? I did a little quick calculation. If you look at the receipt budget... ...(Time-bell)...

Sir, this is important stuff. This is for your State and mine and every one else. Our money is being taken away. Let us pay attention.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Okay.

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: So, basically, if they are aiming to raise Rs. 1.13 lakh crore in this year from this item, well, at eight rupees per litre it is about 14,125 crore litres. 42 per cent of the two rupees per litre would be 84 paise. If you multiply that, States together lose Rs. 11, 885 crore. For what — just so that the Centre can take away money that should have come to each of our States. This is outrageous and I demand that the Finance

Minister makes a change in this provision before the Budget or the Finance and Appropriation Bills are actually passed.

Sir, like Mr. Vijayasai Reddy, I have two-three last points to make. So, give me two-three minutes more.

Sir, education is my pet subject. That is my old profession. This Budget has seen the lowest allocation to education as a proportion of the total Budget in the last eight years. That is shameful. UPA had an average of 4.5 per cent of the Budget and NDA is averaging only 3.6 per cent. What are they trying to do to the people of India? They promised in their manifesto six per cent of GDP on education. Instead we see 3.4 per cent of GDP allocated this year. And, this also means that there is another cess there. They have pooled the education and health cess together and there is no clarity on how much would go to health and how much would go to education. We don't know that. There are other programmes — one lakh crore rupees allocated for Revitalizing Infrastructure and Systems in Education and there again, there is no roadmap on how it is going to be expended.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you.

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: No, Sir. There are two or three more urgent issues.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You already said you have two or three more issues when I last told you.

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Sir, if you are a little patient, you would find that this is most important.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): We are patient, but please conclude.

(FOLLOWED BY HK/2X)

HK-HMS/2X/5.55

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Sir, you know when the ship is sinking, the slogan is "Women and children first". When this Government's ship is sinking, they go after the programmes and funding for women and children first. Okay. That is a shame. What have they done? For children, the allocations were 4.6 per cent of the Budget in 2012-13 and it has now come down to 3.23 per cent. ...(Interruptions)...

SHRI AMAR SHANKAR SABLE: Time is over. ...(Interruptions)...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Who are you? ...(Interruptions)... You are not the Vice-Chairman. ...(Interruptions)...

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Sir, they should learn from Karnataka Government which has a rock solid Karnataka State Child Protection Policy. ...(Interruptions)... Sir, Budgetary allocation for the National Commission for Protection of Child Rights has come down; it is 30 per cent lower than the Revised Budget Estimates. ...(Interruptions)... Sir, Economic Survey had a pink cover. That is it. There is nothing in the Budget to match the symbolism of the cover of the Economic Survey and the Government's commitment to women. Sir, maternity benefit scheme has come down by Rs.300 crore; National Commission for Women has seen a decline; their Nirbhaya Funds Scheme has come down and girls' education has seen 20 per cent reduction. सर, "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" क्या है? Why 20 per cent reduction for that? Finally I come to disabled people. I know your own concerns for people who are minorities of various kinds and the disabled also. And here, you will see that the increase in Budgetary support is inadequate and there is a variety of failed promises in terms of escalators in the railways, etc. Sir, I just want to end now. ...(Interruptions)...

SHRI AMAR SHANKAR SABLE: Time is over. ...(Interruptions)...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: What is this? ...(Interruptions)... Who is he? ...(Interruptions)...

SHRI AMAR SHANKAR SABLE: Who are you? ...(Interruptions)... I am speaking to the Chair. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please sit down. ...(Interruptions)... I will take care. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)...

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: Sir, I want to conclude. ...(Interruptions)... May I conclude? ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): By this time, you would have concluded. ...(Interruptions)... By this time, you would have concluded. ...(Interruptions)... Don't waste the time. ...(Interruptions)..., Please sit down. ...(Interruptions)...

श्री नीरज शेखर : बी0जे0पी0 के लोगो, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। वे इस सदन की सब से वरिष्ठतम महिला हैं।

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA: I want to point out one thing that in the other House the Prime Minister quoted Basavanna, our great social reformer from Karnataka. Sir, in one of his famous *Vachanas*, Basavanna says:

kalabeda kolabeda

husiya nudiyalu beda

'*Husiya nudiyalu beda*' means 'do not utter falsehoods'. Sir, this Government's promises during their election campaigns, their actual practice during the Budget, the statement outside and the statement inside, are all falsehoods. They will come face to face with the truth in the coming elections starting from Karnataka. ...(Interruptions)... Sir, we will show them. ...(Interruptions)... Thank you.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Rajeev Gowda*ji*; now, Shri Joy Abraham; not present. Dr. Sushil Gupta; this is your maiden speech. You will be given fifteen minutes. Kindly conclude within time.

डा0 सुशील गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय और सदन में उपस्थित सभासदो, मैं इस सदन में पहली बार बोल रहा हूं और संसदीय जीवन के हिसाब से मेरी सब से कम उम्र है, इसलिए मैं कुछ गलत कह जाऊं, तो आप सब मुझे excuse करें।

महोदय, मैं मानता हूं, मुझे मालूम नहीं कि मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर और गुरुद्वारे में परमात्मा, अल्लाह, वाहे गुरु हैं या नहीं, परंतु मुझे मालूम है कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, उन के अंदर परमात्मा का अंश है। अब अगर वह अंश निकल जाए तो मानव का शरीर biological degradable body बनकर रह जाता है, जिसे हम घर के अंदर दो घंटे से अधिक नहीं रख सकते। इसलिए इंसान का शरीर चलता-फिरता

मंदिर है और इस मंदिर की सेवा जिस तरीके से हो सकती है, उस में सब से पहले health sector आता है।

मैं सब से पहले health के विषय पर बात करूंगा। भारत सरकार का health के ऊपर टोटल बजट का 2.24 परसेंट बैठता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल ने health के ऊपर बजट का 12 परसेंट लगाया है ताकि हम मानव जीवन को सब से अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकें, मानव जीवन की सब से better care कर सकें। महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि भारत सरकार 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी ला रही है ..

(2 वाई/एएससी पर जारी)